ISSN: 2249-894X IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) VOLUME - 6 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2017

REVIEW OF RESEARCH

भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का गरीबी उन्मूलन में योगदान

डॉ. उमेश कुमार शाक्य
असि प्रोफेसर- अर्थशास्त्र ,
माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय आंवलखेड़ा,
आगरा .

सारांश (Abstract)

भारत में गरीबी उन्मूलन लंबे समय से आर्थिक नीति का प्रमुख लक्ष्य रहा है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। किंतु पारंपरिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार, रिसाव (Leakages), मध्यस्थों की भूमिका तथा लाभार्थियों की गलत पहचान जैसी समस्याएँ सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2013 में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणाली की शुरुआत की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है।

यह शोधपत्र 2013 से 2017 के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के क्रियान्वयन का विश्लेषण करता है और यह मूल्यांकन करता है कि DBT ने गरीबी उन्मूलन में किस प्रकार योगदान दिया है। भारत सरकार की रिपोर्ट, विश्व बैंक, RBI तथा अन्य आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त विश्लेषणों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई है, भ्रष्टाचार और रिसाव को कम किया है तथा सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 2013 से 2017 के बीच DBT के माध्यम से लाखों लाभार्थियों को सीधे सब्सिडी प्रदान की गई और सरकार को हजारों करोड़ रुपये की बचत भी हुई। DBT प्रणाली ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया और जन-धन योजना, आधार और मोबाइल तकनीक के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत किया।

इस सब के बावजूद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के सामने कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे डिजिटल अवसंरचना की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की सीमित पहुँच तथा डिजिटल साक्षरता का अभाव। इन समस्याओं के समाधान के लिए बेहतर तकनीकी ढाँचा, वित्तीय समावेशन और प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। DBT प्रणाली गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति उपकरण सिद्ध हो सकती है।

बीज शब्द (Key Word): गरीबी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, डीबीटी(Direct Benefit Transfer)

1. परिचय (Introduction)

भारत विश्व की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी एक महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौती बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक योजनाएँ लागू की हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), मनरेगा, खाद्य सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन योजनाएँ आदि। यद्यपि इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, लेकिन इनके क्रियान्वयन में लाभार्थियों की गलत पहचान, मध्यस्थों के कारण भ्रष्टाचार, संसाधनों का रिसाव, प्रशासनिक अक्षमता जैसी कई समस्याएँ भी सामने आईं। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणाली लागू की। DBT का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है। यह प्रणाली JAM Trinity (Jan-Dhan, Aadhaar, Mobile) पर आधारित है, जिसने भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया। DBT कार्यक्रम की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। बाद में इसे धीरे-धीरे देश के सभी जिलों और कई कल्याणकारी योजनाओं तक विस्तारित किया गया। DBT का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाना, भ्रष्टाचार और रिसाव को कम करना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाना आदि है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं -

- भारत में DBT प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन करना।
- DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं के वितरण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
- DBT का गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- DBT के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
- DBT प्रणाली की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुझाव देना।

साहित्य समीक्षा

Muralidharan, Niehaus और Sukhtankar (2016) के अनुसार DBT प्रणाली सामाजिक सुरक्षा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष नकद अंतरण प्रणाली विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का एक प्रभावी साधन है क्योंकि यह प्रशासनिक लागत कम करती है और लक्षित लाभार्थियों तक संसाधन सीधे पहुँचाती है।

आँकड़ों के अनुसार DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में सब्सिडी स्थानांतरित की गई, जिससे नकली लाभार्थियों की पहचान हटाई गई और भ्रष्टाचार में कमी आई।

एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2013 से मार्च 2017 के बीच DBT के माध्यम से लगभग "83,184 करोड़ की राशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की गई।

इन अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि DBT प्रणाली सामाजिक सुरक्षा वितरण को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

इस अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है एवं अध्ययन के लिए वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, DBT Bharat Portal, विश्व बैंक रिपोर्ट, RBI रिपोर्ट आदि से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है तथा तुलनात्मक विश्लेषण, प्रतिशत विश्लेषण एवं प्रवृत्ति विश्लेषण आदि विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया गया है।

DBT प्रणाली का विकास

भारत में DBT कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में हुई। प्रारंभ में इसे कुछ योजनाओं में लागू किया गया, लेकिन बाद में इसे व्यापक रूप से विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं में लागू किया गया।

DBT प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभ हैं-1. आधार पहचान प्रणाली 2. बैंकिंग नेटवर्क 3. मोबाइल कनेक्टिविटी। इन तीनों के संयोजन को JAM Trinity कहा जाता है, जिसने DBT प्रणाली को मजबूत आधार प्रदान किया।

डेटा विश्लेषण (Data Analysis)

DBT के माध्यम से स्थानांतरित राशि (₹ करोड़)

वर्ष	राशि
2013–14	7,367
2014–15	38,926
2015–16	61,942
2016–17	74,689

Source: DBT Bharat Portal; World Bank DBT Dataset

DBT के अंतर्गत योजनाओं की संख्या

वर्ष	योजनाएँ
2013	28
2014	34
2015	59
2016	142

Source: Government of India DBT Mission Data

DBT के माध्यम से सरकारी बचत

वर्ष	अनुमानित बचत (₹ करोड़)
2014–15	15,192
2015–16	20,951
2016–17	14,000

Source: Government Estimates reported in Economic Reports

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का गरीबी उन्मूलन में योगदान

भारत में गरीबी उन्मूलन लंबे समय से आर्थिक और सामाजिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार ने समय-समय पर अनेक कल्याणकारी योजनाएँ और सब्सिडी कार्यक्रम लागू किए हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेंशन योजनाएँ, छात्रवृत्ति और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ। हालांकि, इन योजनाओं के पारंपरिक क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, मध्यस्थों की भूमिका, संसाधनों का रिसाव तथा वास्तविक लाभार्थियों तक सहायता न पहुँच पाने जैसी समस्याएँ सामने आती रही हैं। इन चुनौतियों को कम करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणाली लागू की।

DBT का मुख्य उद्देश्य सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना है। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार और लाभार्थी के बीच मौजूद मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है, जिससे भ्रष्टाचार और संसाधनों के दुरुपयोग में कमी आती है। DBT प्रणाली मुख्यतः जन-धन खाते, आधार पहचान और मोबाइल तकनीक (JAM Trinity) पर आधारित है, जिसने डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत किया है।

गरीबी उन्मूलन में DBT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि यह सरकारी सहायता को सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, एलपीजी सब्सिडी, छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था पेंशन और मनरेगा जैसी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में जमा किए जाते हैं। इससे लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती है और उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इसके अतिरिक्त DBT प्रणाली ने वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे गरीब वर्ग औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सका। इससे बचत की आदत बढ़ी और लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलने लगा।

हालाँकि DBT प्रणाली के सामने कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना की कमी, बैंकिंग सुविधाओं की सीमित उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता का अभाव। फिर भी इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली ने सरकारी योजनाओं के वितरण को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाया है। यह प्रणाली न केवल भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक है बल्कि गरीबों तक सरकारी सहायता पहुँचाकर गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) की चुनौतियाँ/समस्याएँ

भारत सरकार ने सरकारी सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। DBT ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ और समस्याएँ सामने आती हैं।

- सबसे बड़ी चुनौती डिजिटल अवसंरचना की कमी है। भारत के कई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधाएँ अभी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण कई लाभार्थियों को अपने बैंक खातों की जानकारी प्राप्त करने या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई होती है।
- एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या बैंकिंग सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या कम होने के कारण लोगों को अपने खातों से पैसे निकालने के लिए लंबी दूरी तय

करनी पड़ती है। इससे गरीब और वृद्ध लाभार्थियों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

- आधार प्रमाणीकरण से संबंधित तकनीकी समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। DBT प्रणाली आधार पहचान पर आधारित है, लेकिन कई बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में त्रुटियाँ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, वृद्ध व्यक्तियों या श्रमिकों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट न होने के कारण उनका प्रमाणीकरण सफल नहीं हो पाता, जिससे उन्हें समय पर लाभ नहीं मिल पाता।
- डिजिटल साक्षरता का अभाव भी DBT की राह में एक गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग बैंकिंग और डिजिटल तकनीक के उपयोग से परिचित नहीं हैं। इस कारण वे अपने खातों की जानकारी, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग का सही उपयोग नहीं कर पाते।
- इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान में त्रुटियाँ भी DBT प्रणाली के क्रियान्वयन में बाधा बनती हैं। कई बार वास्तविक लाभार्थियों के नाम सूची में शामिल नहीं होते, जबकि कुछ अपात्र लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं। इससे योजनाओं की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

अंततः कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली सरकारी योजनाओं के वितरण में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना, तथा लोगों में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए तो DBT प्रणाली गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बना सकती है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) की चुनौतियों हेतु समाधान/उपाय/सुझाव

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली प्रभावी क्रियान्वयन में कई समस्याएँ आ रही हैं जिनको दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय और सुझाव निम्नलिखित हैं-

- सबसे पहले डिजिटल अवसंरचना का विस्तार करना आवश्यक है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधाओं को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को ब्रॉडबैंड और डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को तेजी से लागू करना चाहिए, ताकि लाभार्थियों को DBT से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करने में सुविधा मिल सके।
- एक महत्वपूर्ण उपाय बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं, बैंक मित्रों (Bank Mitra) और एटीएम की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इससे लाभार्थियों को अपने खातों से धन निकालने में आसानी होगी और उन्हें लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही मोबाइल बैंकिंग और माइक्रो-एटीएम जैसी सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग बैंकिंग प्रणाली और डिजिटल तकनीक से परिचित नहीं होते हैं। इसलिए सरकार और गैर-सरकारी संस्थाओं को मिलकर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिससे लोगों को बैंकिंग सेवाओं, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और आधार प्रमाणीकरण की जानकारी मिल सके।
- आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। कई बार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में तकनीकी समस्याएँ आती हैं। इसके समाधान के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण विधियाँ जैसे ओटीपी आधारित सत्यापन और अन्य पहचान प्रणालियाँ भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

- इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की सही पहचान और डेटा प्रबंधन में सुधार भी आवश्यक है। सरकारी विभागों को लाभार्थियों की सूची को नियमित रूप से अद्यतन करना चाहिए ताकि केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजनाओं का लाभ मिल सके।

अंततः कहा जा सकता है कि DBT प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल अवसंरचना का विकास, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना तथा तकनीकी प्रणाली में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है । यदि इन उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो DBT प्रणाली न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाएगी बल्कि गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

यह अध्ययन दर्शाता है कि DBT प्रणाली भारत में सामाजिक सुरक्षा वितरण में एक महत्वपूर्ण सुधार है। 2013 से 2017 के बीच DBT के माध्यम से सरकारी सब्सिडी का वितरण अधिक पारदर्शी और प्रभावी हुआ है। DBT ने सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने में मदद की है और इससे भ्रष्टाचार तथा संसाधनों के रिसाव में कमी आई है। उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि DBT ने प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है यद्यपि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि इसके क्रियान्वयन में अभी भी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन उचित नीति सुधार और तकनीकी विकास के माध्यम से DBT प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है जिससे दीर्घकाल में यह प्रणाली भारत में समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ (References)

1. Government of India. (2017). *Direct Benefit Transfer Mission Report*. New Delhi: Ministry of Finance.
2. Muralidharan, K., Niehaus, P., & Sukhtankar, S. (2016). Building state capacity: Evidence from biometric smartcards in India. *American Economic Review*, 106(10), 2895–2929.
3. World Bank. (2017). *Direct Benefit Transfer and Social Protection in India*. Washington DC.
4. Reserve Bank of India. (2016). *Report on Financial Inclusion*. Mumbai: RBI.
5. NITI Aayog. (2017). *Evaluation Study on Direct Benefit Transfer*. Government of India.